स्वतंत्र सोच, निष्पक्ष अभिव्यक्ति

RNI Regd. No. 7756/59

63वां वर्ष

दण्डकारण्य समाचार

जगदलपुर व रायपुर से एक साथ प्रकाशित

जगदलपुर, गुरुवार 14 जनवरी 2021 ■ वर्ष 63 ■ अंक 03 ■ पृष्ठ 12 ■ मूल्य 2.00 ■ संस्थापक - स्व. श्री तुषार कांति बोस

राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने मकर संक्रांति एवं पोंगल पर्व की दी शुभकामनाएं

रायपुर, 13 जनवरी । राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मकर संक्रांति एवं पोंगल पर्व पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि देश के विभिन्न प्रान्तों में अलग-अलग नामों से मनाये जाने वाले संक्रांति, पोंगल, माघ बीहू जैसे पर्व भारत की सांस्कृतिक एकता को प्रदर्शित करते हैं और हमें एकता के सूत्र में बांधे रखते हैं। राज्यपाल ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की है।

महाराष्ट्र के मंत्री मुंडे पर रेप का आरोप

मुंबई ,13 जनवरी (ए)। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे पर एक गायिका ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। युवती ने मुंबई के ओशिवरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दी है। पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दयानंद बांगर ने शिकायत मिलने की पुष्टि की है। गायिका युवती ने धनंजय मुंडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करने पर ट्वीट किया कि अब तक न तो पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया है और न ही कोई कार्रवाई की है। गायिका का आरोप है कि वह साल 1997 में अपनी बहन के घर इंदौर गई थी। तब वह 16-17 साल की थी। मुंडे की उनकी बहन करुणा शर्मा के साथ साल 1998 में प्रेम विवाह हुआ था। साल 2006 में जिस समय उसकी बहन डिलीवरी के लिए इंदौर गई थी उस वक्त वह घर पर अकेली थी। इसी दौरान धनंजय मुंडे रात में उसके घर पर आए और इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए।

नाबालिग दिव्यांग से सामूहिक दुष्कर्म

पटना ,13 जनवरी (ए)। बिहार के मधुबनी जिले में चारा लेने गई 17 साल की दिव्यांग किशोरी से कुछ लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद पहचान छिपाने के लिए उसकी आंखों को निर्दयता से लकड़ी का टुकड़ा घुसाकर फोड़ दिया और मरने के लिए फेंककर फरार हो गए। किशोरी को दरभंगा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है।

वैक्सीन का पहला खेप पहुंचा छग

रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के जिलों को वितरण शुरू

आज बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों में भेजे जाएंगे

रायपुर, 13 जनवरी । छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आज पहुंच गई है। राज्य वैक्सीन भंडार से जिलों को टीकों का वितरण भी शुरू कर दिया गया है। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. अमर सिंह ठाकुर ने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित 'कोविशील्ड' के तीन लाख 23 हजार टीके प्रदेश को मिले हैं। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के जिलों को इनका वितरण आज ही शुरू कर दिया गया है। बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों में 14 जनवरी को ये टीके भेजे जाएंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कार्मिकों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये टीके लगाए जाएंगे।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रोटोकॉल के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में इन टीकों के परिवहन और भंडारण की पुख्ता व्यवस्था की गई है। सभी जिलों में टीकाकरण के लिए मॉकड्रिल और आपात स्थिति से निपटने का पूर्वाभ्यास भी किया जा चुका है। राज्य वैक्सीन भंडार से जिलों तक वैक्सीन भेजने के लिए इंसुलेटेड वैक्सीन वेन की व्यवस्था की गई है। इसके लिए एक राज्य स्तरीय, तीन क्षेत्रीय और 27 जिला स्तरीय कोल्ड चैन प्वाइंट्स बनाए गए हैं। प्रदेश में टीकों के सुरक्षित भंडारण व परिवहन के लिए अभी 630 क्रियाशील कोल्ड चेन प्वाइंट एवं 85 हजार लीटर से अधिक कोल्ड चैन स्पेस उपलब्ध है। इनके साथ ही 81 अतिरिक्त कोल्ड चैन प्वाइंट भी स्थापित किए गए हैं। वैक्सीन के परिवहन के लिए 1311 कोल्ड-बॉक्स उपलब्ध हैं। सीरिंज, नीडल एवं अन्य सामग्रियों के भंडारण के लिए प्रदेश भर में 360 ड्राई-स्टोरेज भी बनाए गए हैं।

प्रदेश में वैक्सीन लांच के लिए 99 स्थल चिन्हांकित किए गए हैं जहां कुल दो लाख 67 हजार 399 हेल्थ-केयर वर्करों, राज्य व केंद्रीय कर्मचारियों तथा सशस्त्र बलों को टीके लगाए जाएंगे। इन सब की जानकारी कोविन पोर्टल में एंट्री की गई है। टीकाकरण के लिए 7116 टीकाकरण कर्मियों को चिन्हांकित कर इसका प्रशिक्षण दिया गया है। सभी 28 जिलों में 83 स्थानों पर कोविड-19 टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया जा चुका है।

टीकाकरण के बाद किसी भी तरह की प्रतिकूल घटना या आपात स्थिति के प्रबंधन के लिए राज्य स्तर से लेकर टीकाकरण स्थलों तक एईएफआई प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है। सभी टीकाकरण केंद्रों को नजदीकी एईएफआई प्रबंधन प्रणाली जैसे मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जोड़ा गया है।

सीबीएसई 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए 18 जनवरी से खुलेंगे स्कूल

नयी दिल्ली,13 जनवरी (ए)। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) परीक्षाओं और अन्य प्रैक्टिकल के मद्देनजर 10वीं और 12 वीं क्लास के लिए 18 जनवरी से प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, काउंसिलिंग आदि के लिए स्कूल खोलने की अनुमति देने का बुधवार को एलान किया।

शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज ट्वीट करके इसकी जानकारी दी।

श्री सिसोदिया ने कहा,ज्ज दिल्ली में सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं और प्रैक्टिकल के मद्देनज़र 10वीं और 12 वीं क्लास के लिए 18 जनवरी से प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, काउंसिलिंग आदि के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी जा रही है।अभिभावकों की सहमति से ही बच्चों को बुलाया जा सकेगा।बच्चों को आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

सरका से इस संबंध में एक मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की गई है जिसका पालन सभी स्कूलों को करना होगा। कौन से बच्चे स्कूल आ रहे हैं, इसका रिकॉर्ड रखना होगा मगर इसे हाजिरी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा

एसओपी के अनुसार, स्कूल प्रांगण में कोरोना के लक्षण वाले किसी बच्चे-कर्मचारी को आने की इजाजत नहीं होगी। प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। स्कूल के प्रवेश, क्लासरुम, प्रयोगशाला और जन सुविधाओं वाली जगहों पर हाथ सैनिटाइजेशन का इंतजाम अनिवार्य है। केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूल ही खुलेंगे। इसके अलावा, कंटेनमेंट जोन में रहने वाला कोई भी शख्स स्कूल नहीं आ सकेगा। कक्षाओं और प्रयोगशालाओं में इंतजाम इस तरह से करना होगा कि कोविड के दिशानिर्देश टूटने न पाए। कर्मचारी को भी समय सारिणी के हिसाब से बुलाया जा सकता है।

कृषि कानूनों की प्रतियां जला कर लोहड़ी मनाते धरना दे रहे किसान

नयी दिल्ली ,13 जनवरी (ए)। दिल्ली सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि वह लोहड़ी के मौके पर प्रदर्शनस्थलों पर नए कृषि कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। वसंत की शुरुआत में अधिकतर उत्तर भारत में लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन लोग लकड़ियां इकट्ठी करके जलाते हैं और सुख एवं समृद्धि की कामना करते हैं। किसान नेता मंजीत सिंह राय ने बताया कि सभी प्रदर्शन स्थलों पर आज शाम कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर वे लोहड़ी मनाएंगे। प्रदर्शन कर रहे 40 किसान संगठनों का शीर्ष संगठन 'संयुक्त किसान मोर्चा' आज दिन में आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठक भी करेगा। किसान संगठनों ने कल कहा था कि वे उच्चतम न्यायालय की तरफ से गठित समिति के समक्ष पेश नहीं होंगे और आरोप लगाया कि यह ''सरकार समर्थक'' समिति है। किसान संगठनों ने कहा कि उन्हें तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। उन्होंने तीन कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाए जाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत किया। हालांकि समिति के सदस्यों की निष्पक्षता पर भी संदेह जताया है। उच्चतम न्यायालय ने तीन नये कृषि कानूनों को लेकर केन्द्र सरकार और दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे रहे किसान संगठनों के बीच व्याप्त गतिरोध खत्म करने के इरादे से मंगलवार को इन कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगाने के साथ ही किसानों की समस्याओं पर विचार के लिये चार सदस्यीय समिति का गठन किया था।

वायु सेना को मिलेंगे 83 तेजस लड़ाकू विमान

सुरक्षा समिति ने लगायी मुहर

नयी दिल्ली 13 जनवरी (ए)। लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही वायु सेना को जल्द ही देश में बने 83 तेजस लड़ाकू विमान लेंगे जिस पर करीब 48 हजार करोड़ रूपये की लागत आयेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक में इस खरीद को मंजूरी दी गयी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद ट्विट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मामलों की समिति ने वायु सेना के लिए 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस की खरीद को मंजूरी दे दी है। अब तक के सबसे बड़े घरेलू सैन्य सौदे पर 48 हजार करोड़ रूपये की लागत आने की संभावना है। ये विमान रक्षा क्षेत्र के सरकारी उपक्रम एचएएल से खरीदे जायेंगे। उन्होंने कहा कि यह सौदा रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में देश के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में 'गेम चेंजर' साबित होगा।

श्री सिंह ने कहा कि जिन स्वदेशी तेजस मार्क - 1 ए विमानों की खरीद की मंजूरी दी गयी है वे आने वाले समय में वायु सेना की रीढ बनकर उभरेंगे। चौथी पीढी के ये लड़ाकू विमान ऐसी अनेक नयी प्रौद्योगिकियों से लैस हैं जो भारत में पहले नहीं थी। तेजस मार्क -1ए में इस्तेमाल किये गये कलपुर्जों और प्रौद्योगिकी में से 50 फीसदी स्वदेशी है जिसे जल्द ही बढाकर 60 फीसदी किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि एचएएल ने नासिक और बेंगलुरू डिविजन में भी पहले ही विनिमार्ण इकाईयों की स्थापना कर ली हैं और वह वायु सेना को इन विमानों की समय पर आपूर्ति के लिए तैयार है। आज के इस निर्णय से एलसीए इकोसिस्टम का विस्तार होगा और रोजगार के नये अवसर पैदा करने में सहायक रहेगा।

रक्षा मंत्री ने कहा कि एलसीए तेजस कार्यक्रम भारत में एयरोस्पेस विनिर्माण इकोसिस्टम को गतिशील आत्मनिर्भर इकोसिस्टम में बदलने में उत्प्रेरक की भूमिका निभायेगा।

वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग

भारत और अमीरात के बीच हुआ समझौता

नई दिल्ली ,13 जनवरी (ए)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और संयुक्त अरब अमीरात के नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी के बीच विज्ञान एवं तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी।

इस समझौता ज्ञापन के तहत जानकारी, आंकड़ों और मौसम विज्ञान, भूकंप विज्ञान और समुद्र विज्ञान से संबंधित उत्पादों जैसे रेडार, उपग्रह और ज्वार मापने वाले उपकरण तथा भूकंप और मौसम विज्ञान केन्द्रों के संबंध में आदान-प्रदान का प्रस्ताव है।

वैज्ञानिकों अनुसंधानकर्ताओं और विशेषज्ञों आदि की अनुसंधान, प्रशिक्षण, सलाह-मशविरे आदि के लिए दोनों देशों के बीच यात्राएं और अनुभवों का आदान-प्रदान, जलवायु संबंधी जानकारी पर केन्द्रित सेवाओं, उष्णकटिबंधीय तूफान की चेतावनी से संबंधित उपग्रह डाटा का उपयोग करने के संबंध में आदान-प्रदान।

द्विपक्षीय वैज्ञानिक और तकनीकी संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं/ सम्मेलनों का आयोजन और दोनों देशों के समान हित के विषयों तथा समझौता ज्ञापन में वर्णित सहयोग के क्षेत्रों के संबंध में मौजूद समस्याओं पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया जाना। दोनों पक्षों द्वारा आपसी तौर पर सहमति बनाकर अन्य क्षेत्रों में सहयोग। आपसी सहमति से समुद्री जल पर समुद्र विज्ञान पर्यवेक्षण नेटवर्क स्थापित करना। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्रभावित करने वाली ओमान सागर और अरब सागर में उठने वाली सुनामी के अधिक विश्वसनीय और तीव्र पूर्वानुमान के लिए सुनामी मॉडल के बारे में अनुसंधान की विशिष्ट क्षमता के निर्माण में सहयोग।

हठधर्मिता छोड़ किसानों की बात मान ले केंद्र - मुख्यमंत्री

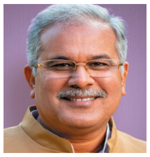

◆ छत्तीसगढ़ की नीतियों पर अमल करे तो किसान आंदोलन ही नहीं करेंगे

रायपुर, 13 जनवरी । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यदि केद्र सरकार छत्तीसगढ़ की नीतियों पर अमल करे तो किसानों को कभी आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र को अपनी हठधर्मिता छोड़कर डेढ़ महीने से आंदोलन पर बैठे किसानों की बात मान लेनी चाहिए। दलहन-तिलहन सहित सभी फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था करनी चाहिए।

बघेल ने यह बात आज महाराष्ट्र के संगमनेर में आयोजित एक समारोह में कही। यह समारोह महाराष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सहकारिता आंदोलन के प्रणेता स्व. भाऊ साहेब थोर्रात तथा हरित-क्रांति में अपने योगदान के लिए याद किए जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. अन्ना साहेब शिंदे की जंयती पर आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि किसानों के हक की लड़ाई सभी को मिल कर लड़ना होगा। देश के किसान-मजदूर मजबूत होंगे, तो देश मजबूत होगा। यदि वे कमजोर होंगे तो देश कमजोर होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र का रवैया बिलकुल ठीक नहीं है, मैं इसकी निंदा करता हूं। बघेल ने कहा कि दिल्ली में आंदोलन पर बैठे किसान केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि 1955 में नेहरू जी द्वारा लागू किया गया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट यदि खत्म कर दिया गया तो सारा अनाज पूंजीपतियों के हाथों में चला जाएगा। महंगाई बढ़ते देर नहीं लगेगी।

आज का इतिहास

1992 इसरायल ने जार्डन के साथ शांतिवार्ता शुरू को पोलैंड के एक जहाज के बाल्टिक सागर में डूब जाने से 54 लोग मारे गए।

1999 देश का पहला अत्याधुनिक हवाई यातायात परिसर (दिल्ली) राष्ट्र को समर्पित।

2002 रक्षा मंत्री जार्ज फर्नान्डीज ने कहा कि आतंकवाद समाप्ति के बाद ही सेना सीमा से हटेगी।

2005 जम्मू-कश्मीर में दो मुठभेड़ों में पांच आतंकवादी मारे गए।

बहुत खूब

भारत को दोस्त बताकर नेपाली पीएम को सख्त संदेश

यहां पत्थर मारकर जानते है गर्भ में लड़का है या लड़की

नई दिल्ली, 13 जनवरी (ए)। आमतौर पर हम सब जानते हैं कि लोग गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग पता करने के लिए सोनोग्राफी का सहारा लेते हैं। हालांकि कन्या भ्रूण हत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। लेकिन झारखंड के लोहरदगा में एक गांव के लोग लिंग का पता करने के लिए एक ऐसा तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे।

दरअसल, झारखंड के लोहरदगा स्थित खुखरा गांव में एक ऐसी पहाड़ी भी है जो गर्भ में पल रहे नवजात लड़का है या लड़की इस बारे में बता देती है। जी हां, आपको शायद यह बात अजीब लगे लेकिन ये सच है। दरअसल, यहां के लोगों का कहना है कि, एक पैसा खर्च किए बिना हम यह पता कर सकते हैं। यह परंपरा यहां चार सौ साल पहले नागवंशी राजाओं के शासन काल से अब तक चल रही है। लोगों के अनुसार ये पर्वत बीते 400 सालों से लोगों को उनके भविष्य के संबंध में जानकारी दे रहा है। गांव के लोगों में इस पर्वत के प्रति अटूट श्रद्धा है।

इस पहाड़ी को लेकर यहां के लोगों के लिए बहुत आस्था है, उनका कहना है कि इस पर चांद के आकार की आकृति बनी हुई है जो नवजात के 'लिंग' के बारे में बताती है। जानकारी के लिए बता दें कि, इस पहाड़ी पर पत्थर मारकर इस बात की जांच की जाती है। गर्भवती महिला एक निश्चित दूरी से पत्थर को इस पहाड़ी पर बने चांद की ओर मारती है। अगर पत्थर चंद्रमा के आकार के ठीक बीच में जाकर लगा तो लोग समझ जाते हैं कि गर्भ में लड़का है और अगर वह पत्थर चंद्रमा के बाहर लगे तो मानते हैं कि गर्भ में पल रही नवजात लड़की है।

उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे की मार से जूझ रहे लोग

◆ मौसम विभाग ने पंजाब-हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

नई दिल्ली ,13 जनवरी(ए)। दिल्ली-एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरे का भी सितम जारी है। दिल्ली में आज सुबह का न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी को घने कोहरे की चादर ने ढक रखा है। पूरे उत्तर भारत में कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। बादल छंटने के बाद कोहरे और शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत पंजाब, हरियाणा समेत दिल्ली-एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप चल रहा है।

मौसम विभाग ने अगले चार-पांच दिनों तक शीतलहर की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में भारी शीतलहर की संभावना जताई है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है।

पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन पाला पड़ने का अनुमान है। वहीं दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और एमपी में अगले 4-5 दिन तक शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट है, इस दौरान घने कोहरे का अनुमान भी जताया गया है।

निजी स्कूलों को ऑनलाईन राशि प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना छग

◆ स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने जारी किए 101 करोड़ रुपए

रायपुर, 13 जनवरी । स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत आज प्रदेश के 5 हजार 403 निजी स्कूलों के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति राशि 101 करोड़ रूपए सीधे उनके खाते में ऑनलाईन ट्रान्सफर किए। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जहां सिर्फ कोरोना काल में 51,985 बच्चों को प्रवेश दिलाकर व्यवस्थित तरीके से ऑनलाईन राशि भेजी गई है। अब तक शिक्षा के अधिकार के तहत 33 लाख 65 हजार 552 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उल्लेखनीय है कि शिक्षा के अधिकार के मामले में छत्तीसगढ़ के इस मॉडल को ओडिशा, झारखण्ड और आसाम राज्यों में भी अपनाया जा रहा है। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री के आवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में संचालक लोक शिक्षण एवं समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक जितेन्द्र कुमार शुक्ल, कार्यक्रम के सहायक संचालक एवं नोडल अधिकारी अशोक कुमार बंजारा, सहायक संचालक प्रशांत पाण्डेय, बैंक के अधिकारी और इन्डस एक्शन संस्था के पदाधिकारी उपस्थित थे।

स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार शिक्षा के अधिकार की राशि ऑनलाईन स्कूलों को प्रदान की गई है। मंत्री डॉ. टेकाम ने बताया कि लंबे समय से यह मांग बार-बार आ रही थी कि निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार के तहत् आने वाले वंचित वर्ग के बच्चों की फीस समय पर नहीं मिल पा रही है।

लॉग ऑन करें : दण्डकारण्य समाचार इंटरनेट संस्करण http://www.dandakaranyasamachar.com Go